भेरू सिंह पुत्र कल्याण सिंह

बनाम

राजस्थान राज्य

4 फ़रवरी, 1994

[न्यायमूर्ति, डॉ. ए.एस. आनंद और न्यायमूर्ति, फैज़ान-उद्दीन]

भारतीय दंड संहिता, 1860: धारा 302-हत्या-आरोपी ने अपनी पत्नी और पांच बच्चों की हत्याएं कीं-पहली सूचना ने खुद दर्ज कराई, जिसमें अपराध के मकसद, अपराध करने के तरीके और अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार का खुलासा किया गया-धारा के तहत दर्ज किया गया कबूलनामा 164 सीआरपी सी -ट्रायजे-न्यायिक स्वीकारोक्ति वापस ली गई -चश्मदीद गवाह और अन्य गवाहों की गवाही अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने और गोपनीय बयान की पुष्टि करने में विफल रही -ट्रायल कोर्ट ने हत्या के अपराध के आरोपी को दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई -उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा और सजा सीमित कर दी - माना गया, चश्मदीदों की आंखों की गवाही स्वयं ही दोषसिद्धि का आधार बन सकती है - स्वैच्छिक इकबालिया बयान के लिए पर्याप्त पुष्टि है - निचली अदालतों ने अपराध के आरोपियों को सही ढंग से दोषी ठहराया - आरोपियों को मौत की सजा दी गई।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872: धारा 8, 21, 25, 27-अभियुक्त द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट, स्वीकारोक्ति-स्वीकार्यता-धारण की गई, एफ.आई.आर. पूरी तरह से इकबालिया बयान नहीं है-वह भाग जो स्वीकारोक्ति की श्रेणी में नहीं आता है और जानकारी देता है धारा 8 के तहत आरोपी के खिलाफ उसके आचरण के साक्ष्य के रूप में पुलिस को दिया जाने वाला अधिकार धारा 8 के तहत स्वीकार्य है और जिस हद तक यह प्रकृति में गैर-इकबालिया बयान है, यह धारा 21 के तहत प्रासंगिक होगा।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 164--स्वीकारोक्ति-रिकॉर्डिंग-मजिस्ट्रेट द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां-समझाया गया।

अपीलकर्ता पर आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी और 2 से 14 वर्ष की आयु के पांच बच्चों की हत्या कर दी। हत्याएं करने के बाद, अपीलकर्ता खून से सनी तलवार के साथ पुलिस स्टेशन गया, और इस आशय की पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि 4-5 दिन पहले उसे अपनी पत्नी की बेवफाई के बारे में पता चला और घटना से पहले की रात, जब उसका सामना किया गया उसकी पत्नी ने अपने नाजायज रिश्ते को कबूल कर लिया जिससे वह बहुत परेशान हो गया; अगले दिन जब उसकी पत्नी घर की दीवार के पत्थरों को ठीक कर रही थी, तो उसने उसका सिर गर्दन से काट दिया और पास में खेल रहे अपने चार बच्चों को भी मार डाला। जब वह पांचवें बच्चे को मारने ही वाला था तो उसकी भाभी वहां पहुंच गई और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई. पुलिस ने आरोपी की ही एफआईआर पर मामला दर्ज किया. आरोपी ने खून से सनी तलवार दिखाई जिसे कब्जे में ले लिया गया। जब अपीलकर्ता न्यायिक हिरासत में था, तो धारा 164 सीआरपी सी के तहत उसका कबूलनामा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया था। जांच अभियुक्त के मुकदमे में समाप्त हुई।

मुकदमे के दौरान, अपीलकर्ता की भाभी, पी डब्ल्यू **11**, चश्मदीद गवाह के रूप में पेश हुईं। उसकी गवाही के अनुसार, जब वह कुएं से लौट रही थी, तो उसने देखा कि अपीलकर्ता की पत्नी और उसके चार बच्चों की हत्या कर दी गई थी और वे मृत पड़े थे और उसकी उपस्थिति में अपीलकर्ता ने अपने पांचवें बच्चे की गर्दन पर वार किया; उसने अपीलकर्ता से बच्चे को न मारने का अनुरोध किया लेकिन इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा; हत्या करने के बाद अपीलकर्ता खून से सनी हुई तलवार के साथ उस स्थान से चला गया; तभी उसका पति एक-डेढ़ घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंचा और उसने उसे कहानी सुनाई। हालाँकि अपीलकर्ता धारा **164** सीआरपी सी के तहत दिए गए कबूलनामे से मुकर गया

ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ता को अपराध का दोषी पाया और उसे मौत की सजा सुनाई और सजा की पुष्टि के लिए कागजात उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए। अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष भी अपील दायर की, जिसने दोषसिद्धि को बरकरार रखा, सजा की पुष्टि की और अपील खारिज कर दी। अतः विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा **25** के प्रावधानों के मद्देनजर, प्रथम सूचना रिपोर्ट पर नीचे की अदालतों द्वारा विचार नहीं किया जा सकता था; पीडब्लू **11** एक विश्वसनीय या सच्चा गवाह नहीं था क्योंकि उसे अपीलकर्ता की सजा से लाभ हुआ था; धारा **164** सीआरपी सी के तहत दर्ज किए गए अपीलकर्ता के वापस लिए गए इकबालिया बयान पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे दर्ज करने से पहले मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक सावधानी नहीं बरती गई थी; और यदि इन सभी साक्ष्यों को हटा दिया जाए, तो अपीलकर्ता बरी किए जाने के आदेश का हकदार था। अंत में दया करने और आजीवन कारावास की कम सजा देने की प्रार्थना की गई।

इस न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया

अभिनिर्धारित किया गया: **1.1.** एक स्वीकारोक्ति या स्वीकारोक्ति इसके निर्माता के खिलाफ सबूत है जब तक कि इसकी स्वीकार्यता को कानून के कुछ प्रावधानों द्वारा बाहर नहीं रखा जाता है।

1.2. जहां अभियुक्त स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करता है, उसके द्वारा पुलिस को सूचना देने का तथ्य, साक्ष्य अधिनियम की धारा **27** के मद्देनजर, धारा के तहत उसके आचरण के साक्ष्य के रूप में उसके खिलाफ स्वीकार्य है। अधिनियम के **8** और वें.! जिस हद तक यह प्रकृति में गैर-इकबालियापन है, यह अधिनियम की धारा **21** के तहत भी प्रासंगिक होगा; लेकिन अधिनियम की धारा **25** की रोक के मद्देनजर प्रथम सूचना रिपोर्ट के इकबालिया हिस्से का इस्तेमाल आरोपी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है।

1.3. मौजूदा मामले में, प्रथम सूचना रिपोर्ट में मृतक के साथ अपीलकर्ता के संबंध, अपराध करने के मकसद और उसकी भाभी पीडब्लू **11** की उपस्थिति का खुलासा करने वाले बयान, अपराध करने की स्वीकारोक्ति के बराबर नहीं हैं। कोई भी अपराध. वे बयान प्रकृति में गैर इकबालिया हैं और साक्ष्य अधिनियम की धारा **8** के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अपीलकर्ता द्वारा खून से सनी तलवार को पुलिस स्टेशन में पेश करना और उसकी जब्ती को भी साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों से बचाया जाता है।

1.4. हालाँकि, यह कथन कि हत्याओं को अंजाम देने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया गया था:। साथ ही अपराध करने का तरीका साक्ष्य में स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है।

2.1. उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा **164** के तहत दर्ज किए गए इकबालिया बयान पर सही भरोसा किया, यह मानते हुए कि यह स्वैच्छिक था और अपीलकर्ता द्वारा बिना किसी धमकी या डर के दिया गया था और इसमें अपराध की पूरी स्वीकारोक्ति थी और इसमें तरीके का भी खुलासा किया गया था। जो अपराध किया गया था.

2.2. मजिस्ट्रेट ने धारा **164,** सीआरपी सी के तहत बयान दर्ज करने से पहले धारा **164 (3)** द्वारा परिकल्पित औपचारिकताओं का पालन किया था। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती थीं कि अपीलकर्ता के पास अपना इकबालिया बयान देने से पहले विचार करने के लिए पर्याप्त समय था और वह व्यापक नहीं था। बयान देने के लिए अदालत में पेश होने से पहले डर या धमकी या प्रलोभन। मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलकर्ता से पूछे गए विभिन्न प्रश्नों से संकेत मिलता है कि उसने इकबालिया बयान देने से पहले अपीलकर्ता से किसी भी तरह के डर को दूर करने के लिए सभी उचित सावधानियां बरती थीं। सावधानी धारा **164** सीआरपी सी द्वारा परिकल्पित उसे उचित रूप से प्रशासित किया गया था और उसे बिना किसी अनिश्चित शब्दों के बताया गया था कि वह एस.बी.टीमेंट बनाने के लिए बाध्य नहीं था और यदि उसने एक बनाया, तो इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा सकता है।

2.3. धारा **164** सीआरपी सी के तहत दर्ज किए गए अपीलकर्ता के स्वैच्छिक इकबालिया बयान के लिए रिकॉर्ड पर प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य पर्याप्त पुष्टि उपलब्ध है, भले ही मुकदमे में मुकर गया हो। **[575-**डी] **3.** अपीलकर्ता की भाभी, पीडब्लू **11** की गवाही, जिसे ट्रायल कोर्ट में बार-बार और लंबी जिरह के अधीन किया गया था, अपरिवर्तित रही है। उनका बयान प्रभावशाली है और उनके पास अपीलकर्ता को इतने जघन्य अपराध में झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं था। उसने बच्चे के नाम के संबंध में अपने बयानों में एकमात्र विसंगति को संतोषजनक ढंग से समझाया, उसने खुद हत्या होते देखी थी। उसकी गवाही ने उस समय और अपराध करने के बाद अपीलकर्ता के आचरण को दर्शाया है, और सभी भौतिक विवरणों में अपीलकर्ता के इकबालिया बयान को पर्याप्त पुष्टि प्रदान करती है। पीडब्लू **11** की नेत्र संबंधी गवाही में कोई दोष नहीं है और वह पूरी तरह से विश्वसनीय गवाह है, यह अपने आप में पांचवें बच्चे की हत्या के लिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराने का आधार बन सकती है। इसके अलावा, पीडब्लू **12** और पीडब्लू **13** ने भी उसकी गवाही के साथ-साथ अपीलकर्ता के इकबालिया बयान को पर्याप्त पुष्टि दी है।

4. उच्च न्यायालय सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट पर भरोसा करने में सही था जिसने स्थापित किया कि अपीलकर्ता के कपड़े और उसके द्वारा बनाई गई तलवार 'बी' समूह के मानव रक्त से सने हुए थे जो कि रक्त समूह के रक्त समूह से मेल खाते थे। मृत व्यक्ति. रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी गई और अपीलकर्ता के इकबालिया बयान को पर्याप्त पुष्टि मिलती है। पीडब्लू **17** द्वारा पुलिस स्टेशन में अपीलकर्ता से खून से सनी तलवार की बरामदगी के स्वामित्व पर संदेह करने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है। जांच के दौरान की गई जब्ती पर भी संदेह नहीं किया गया है। **(574-**सी-ई] **5.** नीचे की अदालतें सही हैं प्रत्येक मामले में अपीलकर्ता को धारा **302** आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे स्थापित किया है कि अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी और पांच बच्चों की हत्या की थी। ऐसी कोई दुर्बलता या संदिग्ध परिस्थिति नहीं है जो किसी भी तरह से हो मुकदमे में प्रस्तुत अभियोजन पक्ष के बयान पर कोई संदेह न करें।

6. जहां तक सजा का सवाल है, अपीलकर्ता ने सबसे जघन्य, निर्मम और वीभत्स हत्या की। उसने न केवल अपनी पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया, बल्कि हत्या की वारदात को अंजाम दिया और **2** से **14**

साल की उम्र के अपने पांच बच्चों की भी बिना किसी गलती के बेहद क्रूर तरीके से हत्या कर दी। अपीलकर्ता ने जो बर्बर, वीभत्स और जघन्य प्रकार का अपराध किया वह समाज के खिलाफ विद्रोह और मानवीय गरिमा का अपमान है। मामले में कोई कम करने वाली या कम करने वाली परिस्थितियां नहीं हैं और यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें मृत्युदंड के अलावा किसी अन्य सजा की आवश्यकता नहीं है। दया की याचिका अनुचित है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में सहानुभूति की प्रार्थना पूरी तरह से गलत है। दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाता है और निचली अदालतों द्वारा अपीलकर्ता को दी गई मौत की सजा की पुष्टि की जाती है।

धनंजय चटर्जी @ धाना बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, **[1994] 2 सी एस-.सी सी 220, पर भरोसा किया गया।**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 22of1991।

डीबी सीआरएल ए संख्या 161/89, और डीबी सीआरएल रेफरी संख्या 2 1989 में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश 20/8/1990 से।

अपीलकर्ता की ओर से केके मेहरोत्रा।

प्रतिवादी की ओर से सुशील कुमार और आर शशिप्रभु।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

न्यायमूर्ति, डॉ आनंद: विशेष अनुमति द्वारा यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत 1 मई, 1989 को सत्र न्यायाधीश, बूंदी द्वारा दर्ज धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता की सजा को बरकरार रखा गया था और सत्र न्यायाधीश द्वारा उसे दी गई मौत की सजा की पुष्टि 20 अगस्त, 1990 के फैसले से की गई।

2.3 जून 1988 को दोपहर से पहले दिन के उजाले में हुई एक घटना के लिए, अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी श्रीमती काजोदबाई, अपनी दो बेटियों मनराजबाई, उम्र 4 साल और हंसाबाई, उम्र लगभग 7 साल की हत्या कर दी। और उनके बेटे राज बहादुर, उम्र 2 साल, नंद कंवर, उम्र 14 साल और नाथू सिंह, उम्र 8 साल। हत्याएं करने के बाद, अपीलकर्ता खून से सनी तलवार लेकर पुलिस स्टेशन दबलाना गया, जिससे कथित तौर पर हत्याएं की गई थीं और खुद ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। पी-42. अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत खून से सनी तलवार को जब्ती ज्ञापन पूर्व के माध्यम से जब्त कर लिया गया था। पी-9 और अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। अपीलकर्ता द्वारा पहनी गई खून से सनी शर्ट और धोती को भी जब्ती ज्ञापन पूर्व के माध्यम से जब्त कर लिया गया। पी-14. चूंकि अपीलकर्ता के बाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली के समीपस्थ भाग पर कुछ चोटें थीं, इसलिए उसे चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दबलाना द्वारा उसकी जांच की गई। सहायक पुलिस उपनिरीक्षक, दुर्गा शंकर पीडब्लू 17 ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत खून से सनी तलवार को पुलिस स्टेशन में जब्त करने के बाद घटना स्थल, अपीलकर्ता के निवास स्थान पर जाकर एक रिपोर्ट तैयार की। साइट योजना। श्रीमती कजोड़बाई का शव घर में पड़ा हुआ था और उसका सिर शरीर के बाकी हिस्सों से पूरी तरह अलग हो गया था। अन्य शव भी उसी परिसर में और बाहर गली में पड़े थे। सहायक उपनिरीक्षक दुर्गा शंकर ने शवों की जांच रिपोर्ट तैयार की और उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। जांच के दौरान

मृतक के खून से सने कपड़े भी जब्त कर लिए गए। जिस स्थान पर शव मिले थे, उसके पास पड़ी खून से सनी रेत और कुछ अन्य सामान भी जांच अधिकारी ने जब्त कर लिया और सील कर दिया और राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में रासायनिक परीक्षण के लिए भेज दिया। सीरोलॉजिस्ट ने बाद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। पी-12.

3.अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामले का मकसद अपीलकर्ता द्वारा अपनी पत्नी, मृतक काजोदबाई पर बेवफाई का संदेह करना प्रतीत होता है। यह आरोप लगाया गया है कि पंचायत चुनाव के दौरान, दुर्भाग्यपूर्ण घटना से लगभग 4 या 5 दिन पहले, अपीलकर्ता को गांव के कुछ लोगों ने बताया था कि एक राजपूत महिला जिसका गुजर के साथ संबंध था, उसे पंच के रूप में शामिल किए जाने की संभावना है और तब से गाँव में राजपूतों का एक परिवार था और वह स्वयं अपीलकर्ता का था, अपीलकर्ता को संदेह था कि यह उसकी पत्नी हो सकती है जिसे बहला-फुसलाकर ले जाया जा रहा है और उसी रात उसने अपनी पत्नी कजोड़बाई से भोजक के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछताछ की। गूजर, लेकिन उसके सवालों के जो जवाब उसने दिये उससे वह संतुष्ट नहीं था। उसी रात जब वह परेशान मानसिक स्थिति में था, तो उसे अपनी पत्नी से पूछताछ के दौरान यह आभास हुआ कि उसके भोजक गूजर के साथ कुछ अवैध संबंध बन गए हैं और उसके साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसलिए, उन्हें न केवल अपनी पत्नी की निष्ठा पर संदेह था, बल्कि उन्होंने यह भी सोचा कि श्रीमती कजोड़बाई से पैदा हुए पांच बच्चे उनके बच्चे नहीं थे। उन भावनाओं को मन में रखते हुए, उसने अपनी पत्नी और सभी पाँच बच्चों की हत्याएँ कीं, हालाँकि उसके भाई की पत्नी, श्रीमती रत्नाबाई पीडब्लू 1 1, ने उसे अपने बच्चों की हत्याएँ करते हुए देखकर उससे हत्या की ओर न जाने का अनुरोध किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, श्रीमती रत्नाबाई पीडब्लू 1 1 ने अपीलकर्ता को वास्तव में अपने बेटे नाथू सिंह के पीछे तलवार लेकर भागते और खून से सनी तलवार के साथ घर की ओर लौटते देखा। वह मनराजबाई की हत्या की गवाह खुद थी. ट्रायल कोर्ट में, विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष, श्रीमती रत्नाबाई पीडब्लू 11 ने गवाही दी थी कि उसने अपीलकर्ता द्वारा हंसाबाई की हत्या करते हुए देखा था और अन्य लोगों की उसके द्वारा पहले ही हत्या कर दी गई थी।

4.जोर सिंह पीडब्लू 12, अपीलकर्ता के भाई ने वास्तव में अपीलकर्ता को हत्याएं करते हुए नहीं देखा था, लेकिन पीडब्लू 12 के रूप में उपस्थित होकर, उसने मुकदमे में गवाही दी कि घटना के दिन वह ग्राम अकोदा गया था और अपनी वापसी पर दोपहर को गांव से उसने अपीलकर्ता को हाथ में तलवार लेकर बाजार में जाते देखा। इस पक्ष में उनके बेटे भंवर सिंह पीडब्लू 13 ने भी उनका समर्थन किया था, जिन्होंने अपीलकर्ता को खून से सनी तलवार के साथ जाते हुए भी देखा था।

5. अभियोजन पक्ष का यह भी कहना है कि 7 जून 1988 को नारायण सिंह, सर्कल ऑफिसर पीडब्लू 15 ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बूंदी के समक्ष एक आवेदन दिया था जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता एक इकबालिया बयान देना चाहता है और उसे दर्ज किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता उस समय न्यायिक हिरासत में था और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए आवेदन को न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया। 8 जून, 1988 को जब आवेदन न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आया, तो उन्होंने अपीलकर्ता को न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश देते हुए सीआरपीसी की धारा 164 के तहत इकबालिया बयान दर्ज करने के मामले को 13 जून, 1988 तक के लिए स्थगित कर दिया। जब अपीलकर्ता न्यायिक हिरासत से बाहर आया, तो आवश्यक प्रश्न पूछने और अपनी पहचान का खुलासा करने के बाद, मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता को सूचित किया कि वह कोई भी बयान देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन अगर उसने कोई बयान दिया, तो उसे

साक्ष्य के रूप में उसके खिलाफ पढ़ा जा सकता है। . अपीलकर्ता को मामले पर विचार करने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया और आश्वासन दिया गया कि वह न्यायिक हिरासत में वापस चला जाएगा और पुलिस को नहीं सौंपा जाएगा, चाहे उसने इकबालिया बयान दिया हो या नहीं। 14 जून, 1988 को अपीलकर्ता को न्यायिक हिरासत से पेश किया गया था और अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत एक स्वैच्छिक बयान दिया था जिसे विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया था और वह पूर्व है। पी-2. अपीलकर्ता ने निश्चित रूप से मुकदमे में अपना इकबालिया बयान वापस ले लिया।

6.डॉ एसएस भोला की अध्यक्षता में एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया और पीड़ितों के शवों का पोस्टमॉर्टम कराया गया। मेडिकल बोर्ड ने सभी छह मृतकों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सौंप दी।

7.जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, अपीलकर्ता के बड़े भाई जोर सिंह पीडब्लू 12 की पत्नी श्रीमती रत्नाबाई पीडब्लू II घटना के एक हिस्से की प्रत्यक्षदर्शी हैं। विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष मुकदमे के दौरान परीक्षण और जिरह के बाद इस गवाह को 20 फरवरी 1989 को सरकारी वकील द्वारा दिए गए एक आवेदन पर वापस बुलाने की मांग की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि टाइपिंग त्रुटि के कारण , घटना का वर्ष ग़लत टाइप हो गया था। उसे वापस बुला लिया गया और उसका बयान 7 मार्च 1989 को दर्ज किया गया और अपीलकर्ता की ओर से उससे आगे जिरह की गई। उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन किया, जैसा कि इस फैसले के पहले भाग में देखा गया है। श्रीमती रत्नाबाई पीडब्लू 11 को वापस बुलाने के लिए एक और आवेदन दायर किया गया था, लेकिन इस बार आवेदन अपीलकर्ता द्वारा इस आधार पर किया गया था कि उन्होंने धारा 161 सीआरपीसी के तहत अपने पुलिस बयान में दिए गए बयान से अपना संस्करण बदल दिया था, लेकिन चूक के कारण कुछ प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक थे, परीक्षण के दौरान उनसे पूछे जाने के लिए छोड़ दिए गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रायल कोर्ट ने न्याय के हित में, अपीलकर्ता को अपना बचाव करने का पूरा अवसर देने की दृष्टि से, 18 अगस्त, 1989 के एक आदेश द्वारा, श्रीमती रत्नाबाई पीडब्लू 11 को एक बार फिर वापस बुला लिया और उनका बयान आगे दर्ज किया गया। 25 अक्टूबर, 1989 को एक बार फिर उन्होंने अभियोजन पक्ष का पूरा समर्थन किया। उसकी गवाही के अनुसार, वह भेरू सिंह अपीलकर्ता की पत्नी को जानती थी, उसकी भाभी होने के नाते और 'वह भेरू सिंह के पांच बच्चों को भी जानती थी। घटना दिनांक को, जब गवाह कुएं से लौट रही थी तो उसने देखा कि भेरू सिंह की पत्नी और उसके चार बच्चों की हत्या कर दी गई थी और वे मृत पड़े थे और उसकी उपस्थिति में भेरू सिंह ने अपनी पांचवीं संतान हंसाबाई की गर्दन पर वार किया। . उसने अपीलकर्ता से हाथ जोड़कर विनती की और चिल्लाई कि बच्चे को न मारें लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने आगे कहा कि अपीलकर्ता हत्या करने के बाद तलवार के साथ घटनास्थल से चला गया, जो खून से सना हुआ था। सभी मृतकों के कपड़े भी खून से सने हुए थे। जिरह के दौरान, उसने इस सुझाव से इनकार किया कि उसके पति और मृतक के बीच संपत्ति को लेकर कोई विवाद था और यह भी कहा कि उसका पति लगभग एक या एक के बाद उसके आने के बाद घटनास्थल पर आया था। आधे घंटे और उसने उसे कहानी सुनाई थी। अपीलकर्ता के अनुरोध पर गवाह को वापस बुलाया गया और दोबारा जांच की गई, उसने स्पष्ट रूप से कहा, "मुझे भेरू सिंह की जमीन नहीं चाहिए। मैंने वह गांव छोड़ दिया है और एक अलग गांव में रहना शुरू कर दिया है।" उनके बयान का यह हिस्सा पूरी तरह से निर्विवाद और निर्विवाद रहा है। सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए उसके पहले के बयान का एकमात्र हिस्सा जिसमें गवाह का सामना किया गया था, जहां उसने पहले कहा था कि उसने भेरू सिंह को अपनी बेटी मनराजबाई की हत्या करते देखा था, जबकि मुकदमे में उसने कहा था कि उसने हंसाबाई की हत्या देखी थी। उसने बताया कि उसने पुलिस के सामने यह भी

कहा था कि अपीलकर्ता ने उसकी बेटी हंसाबाई की गर्दन पर तलवार से हमला किया था और उसने वास्तव में उसे हंसाबाई पर तलवार से वार करते देखा था, न कि मनराजबाई पर।

8.जोर सिंह पीडब्ल्यू 12 ग्राम अकोदा गया था और जब वह दोपहर के समय उस गांव से लौटा, तो उसने अपीलकर्ता भेरू सिंह को हाथ में तलवार लेकर बाजार से गुजरते देखा और जब वह घटनास्थल पर पहुंचा, तो उसने उनकी पत्नी पीडब्लू II रत्नाबाई से पता चला कि अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी और पांच बच्चों की हत्याएं की थीं। जोर सिंह के बेटे भंवर सिंह पीडब्लू 13 ने यह भी कहा कि उसने अपने चाचा भेरू सिंह-अपीलकर्ता को लगभग 11 या 12 बजे दोपहर में हाथ में तलवार लेकर दबलाना की ओर जाते हुए देखा है। यह कि मृतकों की मृत्यु उनकी गर्दन पर तलवार से लगी चोटों के परिणामस्वरूप हुई और वे चोटें मृत्यु का कारण बनने के लिए प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया में पर्याप्त थीं, यह चिकित्सा साक्ष्य द्वारा स्थापित किया गया है। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में अपीलकर्ता ने इस बात से इनकार किया कि उसने कथित अपराध किया है।

9.कि अपीलकर्ता पुलिस स्टेशन दबलाना गया और न केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई बल्कि पुलिस के सामने खून से सनी तलवार भी पेश की, यह रिकॉर्ड से पूरी तरह से स्थापित है। दुर्गा शंकर शर्मा पीडब्लू 17, सहायक की गवाही। पुलिस थाना दबलाना के उपनिरीक्षक ने खुलासा किया कि अपीलकर्ता के कहने पर ही पूर्व पुलिस अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पी 42 दर्ज किया गया था और अपराध मामला संख्या 40/1988 आईपीसी की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के तहत दर्ज किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के समय अपीलकर्ता द्वारा पेश की गई खून से सनी तलवार को जब्ती ज्ञापन पूर्व द्वारा जब्त कर लिया गया था। पी-9. अपीलकर्ता की खून से सनी शर्ट और धोती भी जब्ती ज्ञापन पूर्व के माध्यम से जब्त कर ली गई। पी-14 और चूंकि अपीलकर्ता के बाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली के समीपस्थ भाग पर कुछ चोटें थीं, इसलिए सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दबलाना के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसकी चिकित्सकीय जांच की गई। अपीलकर्ता के संबंध में चोट की रिपोर्ट उक्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा पूर्व के रूप में साबित की गई थी। पी-18. घटनास्थल पर पहुंचने पर दुर्गा शंकर शर्मा पीडब्लू 17 ने देखा कि कजोड़बाई का सिर बाकी मूडी से कटा हुआ पड़ा था और पास में ही तलवार का एक म्यान भी पड़ा हुआ था। इसे जब्ती ज्ञापन पूर्व के माध्यम से जब्त कर लिया गया। पी-16 और कजोड़बाई, नंद कंवर, मनराजबाई, हंसाबाई, बहादुर सिंह और नाथू सिंह के शवों की जांच रिपोर्ट उनके द्वारा तैयार की गई थी। जांच के दौरान पीडब्लू 17 ने मृत व्यक्तियों के खून से सने कपड़े भी जब्त कर लिए और उस स्थान के पास से जहां शव पड़े हुए थे, खून से सने रेत का नमूना लिया। जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया और सीरोलॉजिस्ट द्वारा रिपोर्ट प्रदर्शनी पी-12 प्रस्तुत की गई।

10. जांच पूरी होने के बाद, आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और प्रतिबद्धता पर विद्वान सत्र न्यायाधीश बूंदी ने अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ता को अपनी पत्नी श्रीमती कजोड़बाई और अपने पांच बच्चों में से प्रत्येक की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध का दोषी पाया और उसके खिलाफ मौत की सजा सुनाई। उन्होंने मौत की सज़ा की पुष्टि के लिए कार्यवाही उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की।

11. उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने पीडब्लू 1 1 की आंखों की गवाही और सीरोलॉजिस्ट एक्स की रिपोर्ट पर भरोसा किया। पी-12 और अपीलकर्ता पूर्व का वापस लिया गया कबूलनामा भी। रिकॉर्ड पर पी-2 और

अन्य सबूतों ने आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता की सजा को बरकरार रखा और अपीलकर्ता द्वारा बिना किसी कारण या कारण के न केवल अपनी पत्नी बल्कि पांच मासूम बच्चों की हत्या की वीभत्स प्रकृति को देखा। इसने उसकी अपील खारिज कर दी और मौत की सजा की पुष्टि की।

12. अपीलकर्ता (ए सी) के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पूर्व। साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों के मद्देनजर पी-42 पर बहुत कम भरोसा किया जा सकता है या इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसे नीचे की अदालतों द्वारा विचार से बाहर कर दिया जाना चाहिए था। विद्वान वकील ने तब प्रस्तुत किया कि रत्नाबाई पीडब्लू 11 एक विश्वसनीय या सच्ची गवाह नहीं है क्योंकि अपीलकर्ता की सजा से उसे लाभ होगा। विद्वान वकील ने अंततः कहा कि अपीलकर्ता पूर्व के वापस लिए गए इकबालिया बयान पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। पी-2, चूंकि अपीलकर्ता का इकबालिया बयान दर्ज करने से पहले विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक सावधानियां नहीं बरती गई थीं और यदि इन सभी साक्ष्यों को बाहर रखा जाता है, तो अपीलकर्ता बरी होने के आदेश का हकदार था। अंत में, विद्वान वकील ने मौत की सजा की पुष्टि न करके और आजीवन कारावास की कम सजा देने पर दया और सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की प्रार्थना की।

13. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मृतक के कपड़ों पर खून के धब्बे का समूह मृतक के खून के समूह के साथ-साथ तलवार पर खून के धब्बे के साथ मेल खाता है, जिसे अपीलकर्ता ने स्वीकार किया था। पीडब्लू 17 के समक्ष पुलिस स्टेशन और वह साक्ष्य पीडब्लू 1 1 की गवाही और स्वैच्छिक इकबालिया बयान के साथ जुड़ा हुआ है, उदा। पी-2 ने उचित संदेह से परे अपीलकर्ता के खिलाफ मामला स्थापित किया था और यह मानते हुए कि अपीलकर्ता ने छह निर्दोष व्यक्तियों की नृशंस हत्या की है, यह दुर्लभतम मामलों में से एक है, जिसमें मौत की सजा की पुष्टि की आवश्यकता थी। इस न्यायालय द्वारा.

14.हमने बार में उठाए गए विवादों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है।

15.इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट उदा. पी-42 को स्वयं अपीलकर्ता ने पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था और श्री दुर्गा शंकर शर्मा पीडब्लू 17 द्वारा दर्ज किया गया था। रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि यह काफी हद तक इकबालिया प्रकृति का है। क्या इसे संपूर्ण या इसके किसी भाग को अपीलकर्ता के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है?

16.एक स्वीकारोक्ति या स्वीकारोक्ति उसके निर्माता के खिलाफ सबूत है जब तक कि उसकी स्वीकार्यता को कानून के कुछ प्रावधानों द्वारा बाहर नहीं रखा जाता है।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 से 30 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के प्रावधान संस्वीकृति से संबंधित हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों के आधार पर, किसी भी परिस्थिति में किसी पुलिस अधिकारी को दी गई स्वीकारोक्ति किसी आरोपी के खिलाफ साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है। यह धारा न केवल तब की गई स्वीकारोक्तियों से संबंधित है, जब आरोपी स्वतंत्र था और पुलिस हिरासत में नहीं था, बल्कि किसी जांच शुरू होने से पहले ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकारोक्तियों से भी संबंधित है। धारा 25 में अभिव्यक्ति "किसी भी अपराध का आरोपी" उस आरोपी के मामले को कवर करेगी जिस पर मुकदमा चलाया जा चुका है, चाहे जिस समय उसने इकबालिया बयान दिया हो, वह गिरफ्तार था या आरोपी के रूप में हिरासत में था। वह मामला है या नहीं. साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत एक पुलिस अधिकारी को दिए गए इकबालिया बयान की अस्वीकार्यता सार्वजनिक नीति के आधार पर है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 न केवल किसी आरोपी द्वारा

किसी पुलिस अधिकारी के सामने अपराध स्वीकार करने या पुलिस अधिकारी की हिरासत में रहने के दौरान अपराध स्वीकार करने पर रोक लगाती है, बल्कि इकबालिया बयान में शामिल सभी आपत्तिजनक तथ्यों को स्वीकार करने पर भी रोक लगाती है। किसी अपराध का घटित होना. साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 एक पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को दी गई स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता पर आंशिक प्रतिबंध से संबंधित है, लेकिन इस मामले में हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 एक परंतुक या अपवाद की प्रकृति में है, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटा देती है और ऐसी बहुत सी जानकारी को स्वीकार्य बनाती है, चाहे वह स्वीकारोक्ति के बराबर हो या नहीं, जैसा कि इस प्रकार खोजे गए तथ्य से संबंधित है, जब पुलिस हिरासत में किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति द्वारा किया गया था। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत जांच के दौरान दिया गया बयान या इकबालिया बयान, मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जा सकता है, जो धारा द्वारा लगाए गए सुरक्षा उपायों के अधीन है और मुकदमे में उस पर भरोसा किया जा सकता है।

17. जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी अभियुक्त द्वारा स्वयं एक पुलिस अधिकारी को दी जाती है और एक इकबालिया बयान के बराबर होती है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 द्वारा बयान का सबूत निषिद्ध है। इकबालिया बयान का कोई भी हिस्सा साक्ष्य में साबित या प्राप्त नहीं किया जा सकता है, सिवाय उस हद तक जब तक कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 द्वारा इसकी अनुमति नहीं है। सीआरपीसी की धारा 154 के तहत दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई ठोस सबूत नहीं है। इसका उपयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत मुखबिर की पुष्टि करने के लिए या साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत उसका खंडन करने के लिए किया जा सकता है, यदि मुखबिर मुकदमे में गवाह के रूप में उपस्थित होता है। जहां अभियुक्त स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराता है, वहां पुलिस को सूचना देने का तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत उसके आचरण के सबूत के रूप में उसके खिलाफ स्वीकार्य है और जिस हद तक यह प्रकृति में गैर-इकबालियापन है, यह होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 के तहत भी प्रासंगिक होगा, लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के प्रतिबंध के मद्देनजर आरोपी द्वारा पुलिस अधिकारी को दी गई पहली सूचना रिपोर्ट का इकबालिया हिस्सा उसके खिलाफ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

18. कानून के उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम पहले अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट का अवलोकन और विचार करेंगे। प्रथम सूचना रिपोर्ट इस प्रकार है:

> "पंचायत चुनाव से ठीक 4-5 दिन पहले गांव के कुछ लोगों ने मुझे ताना मारा कि इस बार के चुनाव में एक राजपूत महिला को 'पंच' के रूप में चुना जाएगा। हमारे गांव में केवल एक राजपूत घर है और मैं और मेरे बुजुर्ग भाई वहीं रहता है। मुझे संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसी रात मैंने अपनी पत्नी कजोड़बाई से इस बारे में पूछताछ की लेकिन उसने किसी भी नाजायज रिश्ते के बारे में इनकार कर दिया लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था और पूछता रहा। आखिरी रात उसने कबूल किया कि उसे भोजन पसंद है फाजलपुरा के गुज्जर और उसके साथ नाजायज संबंध बन गए। इस पर मैं कल रात को बहुत परेशान था। आज जब मेरी पत्नी घर की दीवार के पत्थरों को सही कर रही थी, मैं तलवार लेकर वहां गया और उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया। तलवार का एक ही वार करके। मेरे बच्चे राज बहादुर उम्र 2 साल, नंद कंवर उम्र 14 साल, हंसा उम्र 7 साल वहां खेल रहे थे। मैंने उन्हें भी तलवार से मार डाला। तभी मुझे मेरा 8 साल का बच्चा नाथू मिला जो रेउआ के पेड़ के पास खड़ा था. मैं उसकी ओर दौड़ा और छोटू महाराज के घर के पास पहुंचते ही उसे भी तलवार से मार डाला. 4 साल का बच्चा मनराज चिल्लाया और हैंडपंप की

ओर भागा लेकिन मैंने उसका पीछा किया और उसे भी तलवार से मार डाला। तभी मेरी भाभी रतन कंवर आ गयी और उसने मुझे रोकने की कोशिश की लेकिन मेरे सिर पर शैतान सवार था; मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया और उसके बच्चों को भी दूसरों ने खरीद लिया होगा। मैंने उन सभी को मार डाला है और अब मैं अपनी तलवार सौंपता हूं।"

उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट एक्स. पी-42 दर्ज होने के बाद पुलिस की कार्यवाही इस प्रकार है:

"भेरू सिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी फाजलपुरा ने इस जानकारी के साथ तलवार का निर्माण किया है। यह तलवार खून से सनी हुई है। इसका आधा खून सूख गया है। इसके साथ खून से सने कुछ बाल भी जुड़े हुए हैं। इसका हैंडल लोहे का बना हुआ है और तलवार की लंबाई हैंडल सहित 37 इंच और चौड़ाई 1 1/4 इंच है। भेरू सिंह के बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली उंगली पर अंदर की ओर दो हड्डियां हैं। और उस पर ताजा खून पिघला हुआ है। उसने लंबी बाजू की शर्ट और सफेद शर्ट पहन रखी है। उस पर खून के धब्बे भी नजर आ रहे हैं। उपरोक्त सूचना के आधार पर मुकदमा क्रमांक 40 दिनांक 3 जून 1988 को दर्ज किया गया। आईपीसी की धारा 302 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के साथ पढ़ा गया और कार्यवाही शुरू की गई।" 19.इस प्रथम सूचना रिपोर्ट के सावधानीपूर्वक अवलोकन से हम पाते हैं कि यह हत्या के मकसद और अपीलकर्ता ने छह हत्याएं करने के तरीके का खुलासा करती है। अपीलकर्ता ने खून से सनी तलवार पेश की जिससे उसके अनुसार उसने हत्याएं कीं। हमारी राय में प्रथम सूचना रिपोर्ट उदा. हालाँकि, पी-42 पूरी तरह से इकबालिया बयान नहीं है, लेकिन इसका केवल वह हिस्सा साक्ष्य में स्वीकार्य है जो स्वीकारोक्ति के बराबर नहीं है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों से प्रभावित नहीं है। अपीलकर्ता का मृतक के साथ संबंध; अपराध करने का मकसद और उसकी भाभी पीडब्लू 11 की उपस्थिति किसी भी अपराध को करने की स्वीकारोक्ति के बराबर नहीं है। वे बयान प्रकृति में गैर-इकबालिया बयान हैं और साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अपीलकर्ता द्वारा पुलिस स्टेशन में तलवार का उत्पादन और जब्ती, जो खून से सनी हुई थी, को भी साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों द्वारा बचाया गया है। हालाँकि, यह कथन कि हत्याओं को अंजाम देने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया गया था और अपराध करने का तरीका स्पष्ट रूप से साक्ष्य में अस्वीकार्य है। इस प्रकार, जैसा कि हमने ऊपर देखा है सीमित सीमा तक और उस सीमा तक केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट के अन्य भाग को बचाएं। पी-42 को साक्ष्य से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि बाकी बयान अपराध करने की स्वीकारोक्ति के बराबर है और साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है।

20.आगे बढ़ने से पहले, इस स्तर पर सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए अपीलकर्ता के इकबालिया बयान से निपटना भी उचित होगा। 14 जून 1988 को पी-2। इस संबंध में, अपीलकर्ता पूर्व द्वारा दिए गए बयान के विश्लेषण से पहले। पी-2, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के बयान की जांच करना वांछनीय होगा जिसने इकबालिया बयान दर्ज किया था। पी-2. श्री तारा चंद सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धारा 164 सीआरपीसी के तहत इकबालिया बयान दर्ज किया, पीडब्लू 1 के रूप में उपस्थित होकर, उन्होंने कहा कि 8 जून, 1988 को जब वह मुंसिफ और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के रूप में तैनात थे, सूरजमल कांस्टेबल ने उनके समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपीलकर्ता का बयान अदालत के ड्यूटी घंटे समाप्त होने के बाद से विद्वान मजिस्ट्रेट के आवास पर आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले को 9 जून, 1988 के लिए अदालत में चिपका दिया और पुलिस को यह दिखाने के लिए

अपीलकर्ता का प्रोडक्शन वारंट पेश करने का निर्देश दिया कि वह न्यायिक हिरासत में था। 9 जून, 1988 को, अपीलकर्ता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और अन्य आरोपी व्यक्तियों से अलग रखने का निर्देश दिया गया और मामले की तारीख 13 जून, 1988 तय की गई, जिस तारीख को अपीलकर्ता अपनी अदालत में पेश हुआ और कहा कि वह बनाना चाहता था। एक बयान। पीडब्लू 1 ने गवाही दी कि उसने प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी स्थिति का खुलासा किया और अपीलकर्ता को चेतावनी दी कि "वह बयान देने या न देने के लिए स्वतंत्र है और यदि वह बयान देता है, तो यह उसके खिलाफ पढ़ा जा सकता है"। अपीलकर्ता को यह भी बताया गया कि उसका बयान तभी दर्ज किया जाएगा जब वह स्वेच्छा से और अपनी मर्जी से बयान देना चाहेगा। अपीलकर्ता को 24 घंटे का समय दिया गया था और मजिस्ट्रेट द्वारा जेलर को लिखित रूप में निर्देशित किया गया था कि अपीलकर्ता को अपनी पसंद के स्थान पर जेल में रहने की अनुमति दी जा सकती है ताकि वह इस पर विचार कर सके और इस पर ठंडे दिमाग से विचार कर सके। चाहे वह कबूलनामा करना चाहता हो या नहीं। उन्होंने अपीलकर्ता को आश्वासन दिया कि यदि वह बयान नहीं देना चाहता है तो उसे पुलिस हिरासत में नहीं भेजा जाएगा। अपीलकर्ता को 14 जून 1988 को उनके सामने पेश किया गया और मजिस्ट्रेट के पूछने पर अपीलकर्ता ने बयान देने की इच्छा व्यक्त की। विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता के मन से डर के किसी भी निशान को दूर करने के लिए सभी कदम उठाए और बयान दर्ज करने से पहले सीआरपीसी की धारा 164(3) द्वारा परिकल्पित औपचारिकताओं का पालन किया। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पी-2 मजिस्ट्रेट ने गवाही दी कि अपीलकर्ता ने स्वेच्छा से और हिंदी में बयान दिया था और पूर्व। पी-2 को अपीलकर्ता द्वारा दिए गए तरीके से दर्ज किया गया था।

21.इकबालिया बयान में पूर्व. पी-2 रिकॉर्ड से पता चलता है कि रिकॉर्ड करने से पहले, अपीलकर्ता से कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछे गए थे ताकि उसे आश्वस्त किया जा सके कि वह प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे रहा था और उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। बिना किसी डर के बयान दें. उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें बयान देने के लिए किसी से खतरा है तो अपीलकर्ता ने नकारात्मक जवाब दिया। उन्हें चेतावनी दी गई थी कि वह कोई भी इकबालिया बयान देने के लिए बाध्य नहीं हैं, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया, तो इसे उनके खिलाफ पढ़ा जा सकता है। इसके बाद उन्होंने बयान दिया, जिसमें रामबिलास महाजन और गिर्राज के साथ उन्हें घर से कुएं तक जीप में ले जाने और कुएं पर उनके साथ हुई बातचीत का खुलासा हुआ। उन्होंने आगे कहा कि बातचीत के दौरान गिर्राज ने मुझे अपने आदमियों की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मारने के लिए उन्हें 50,000 रुपये दिए हैं। इसलिए अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम खुद ही अपने परिवार के सदस्यों को मार डालो। ... मैं अपने बच्चों को मारने के लिए तैयार हो गया। गिर्राज ने मुझसे यह भी कहा, तुम्हें अदालत में यह कहना होगा कि तुम्हारी पत्नी बुरे चरित्र वाली थी। ..." उसने आगे कहा, इसके बाद, उसने अपनी पत्नी और बच्चों को उसी तलवार से मार डाला जो उसकी थी। उसे। उसने कहा कि उसने पहले अपनी पत्नी और उसके बाद बच्चों की हत्या की और फिर पुलिस स्टेशन गया और हत्या करने की जानकारी देने के बाद पुलिस के सामने वह तलवार पेश की, जिससे उसने हत्याएं की थीं।

22. उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए इकबालिया बयान पर भरोसा किया और पाया कि यह स्वैच्छिक था और अपीलकर्ता द्वारा बिना किसी धमकी या डर के दिया गया था और इसमें अपराध की पूरी स्वीकारोक्ति थी और इसमें तरीके का भी खुलासा किया गया था। जो अपराध किया गया था. उच्च न्यायालय ने सीरोलॉजिस्ट श्री वी.एन. , जो उस रक्त समूह से मेल खाता था जिसके साथ मृत व्यक्तियों

के कपड़े दागे गए थे। उच्च न्यायालय ने इसे वापस लिए गए इकबालिया बयान पूर्व की पर्याप्त पुष्टि के रूप में माना। पी-2 और अपीलकर्ता पीडब्लू 11 की भाभी की गवाही के साथ-साथ रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सामग्री पर भरोसा करते हुए, पाया गया कि अपीलकर्ता के वापस लिए गए कबूलनामे को प्रत्यक्ष और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य दोनों से पर्याप्त पुष्टि मिली थी। और सत्र न्यायाधीश से सहमत होकर, धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता की सजा को बरकरार रखा

23.हमने अपीलकर्ता के वापस लिए गए न्यायिक बयान पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री तारा चंद सोनी पीडब्लू 1 के बयान का विश्लेषण किया है। हमने इस फैसले के पहले भाग में कुछ विवरणों में इकबालिया बयान का उल्लेख किया है। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती थीं कि अपीलकर्ता के पास अपना इकबालिया बयान देने से पहले विचार करने के लिए पर्याप्त समय था और बयान देने के लिए अदालत में पेश होने से पहले वह किसी डर या धमकी या प्रलोभन में नहीं था। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलकर्ता से पूछे गए विभिन्न प्रश्नों से संकेत मिलता है कि उसने इकबालिया बयान देने से पहले अपीलकर्ता के मन से किसी भी तरह का डर दूर करने के लिए सभी उचित सावधानियां बरती थीं। सीआरपीसी की धारा 164 द्वारा दी गई सावधानी उन्हें उचित रूप से दी गई थी और उन्हें बिना किसी अनिश्चित शब्दों के बताया गया था कि वह बयान देने के लिए बाध्य नहीं थे और यदि उन्होंने ऐसा बयान दिया, तो इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा सकता है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ऐसी किसी भी परिस्थिति को इंगित करने में असमर्थ थे जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि इकबालिया बयान पूर्व। पी-2 स्वैच्छिक नहीं था। बयान दर्ज करने के तरीके या बयान में किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं बताई गई। सीरोलॉजिस्ट श्री वी.एन.माथुर की रिपोर्ट ने स्थापित किया कि अपीलकर्ता की तलवार और साथ ही अभियुक्तों के कपड़े 'बी' समूह के मानव रक्त से सने हुए थे, जो मृत व्यक्तियों के रक्त समूह से मेल खाते थे। चुनौती रहित बने रहने से उस इकबालिया बयान को पर्याप्त पुष्टि मिलती है जिसे अपीलकर्ता ने मुकदमे में वापस लेने की कोशिश की थी। श्री दुर्गा शंकर शर्मा, पीडब्लू 17 द्वारा पुलिस स्टेशन में अपीलकर्ता से खून से सनी तलवार के स्वामित्व और बरामदगी पर संदेह करने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है। जांच के दौरान की गई बरामदगी पर भी संदेह नहीं किया गया है।

24.अपीलकर्ता की भाभी, श्रीमती रत्नाबाई पीडब्लू 11 की गवाही, जिसे ट्रायल कोर्ट में बार-बार और लंबी जिरह के अधीन किया गया था, अपरिवर्तित रही है। उनके बयान ने हमें प्रभावित किया है और हमारी राय में उनके पास अपीलकर्ता को इतने जघन्य अपराध में झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं था। जोर सिंह पीडब्लू 12 और भंवर सिंह पीडब्लू 13 ने उसकी गवाही के साथ-साथ अपीलकर्ता के इकबालिया बयान को पर्याप्त पुष्टि दी है। पीडब्लू 11 के बयान के संबंध में एकमात्र विसंगति यह है कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत अपने बयान में उसने हंसाबाई का नाम उस बच्चे के रूप में लिया था जिसे उसने खुद हत्या होते देखा था, लेकिन मुकदमे में उसने उस बच्चे का नाम हंसाबाई बताया था। मनराज. जब उससे सवाल पूछा गया तो उसने विसंगति के बारे में संतोषजनक ढंग से बताया और अन्यथा भी कोई इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि गवाह ने अपने बहनोई द्वारा अपनी ही पत्नी और बच्चों की सबसे भयानक हत्या देखी थी। इसलिए, बच्चे के नाम की यह मामूली विसंगति महत्वहीन हो जाएगी, खासकर जब हंसा और मनराज दोनों की अपीलकर्ता द्वारा अन्य लोगों के साथ हत्या कर दी गई थी। हमने पाया कि पीडब्लू II रत्नाबाई एक विश्वसनीय गवाह है और उसकी गवाही सभी भौतिक विवरणों में अपीलकर्ता के इकबालिया बयान को पर्याप्त पुष्टि प्रदान करती है।

25. पीडब्लू 14 कान्हा, जो मृतक कजोड़बाई से संबंधित है, ने बताया कि वह मृतक को जानता था और जोर सिंह द्वारा बुलाए जाने पर, जिसने उसे बताया कि अपीलकर्ता ने उसके परिवार की हत्या कर दी है, वह मौके पर आया और कजोड़बाई के मारे गए शवों को देखा। अपीलकर्ता के पांच बच्चे। जब जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे और साइट प्लान तैयार किया तो उनके अंगूठे का निशान लिया गया। उन्होंने घटनास्थल से खून से सनी मिट्टी और मृत बच्चों के कपड़े जब्त करने के बारे में बताया। उनसे जिरह में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जिससे उनकी सत्यता पर कोई संदेह किया जा सके। अपीलकर्ता के बच्चों और उसकी मृत पत्नी के शव घर से और घर के परिसर और गली के बाहर से बरामद किए गए थे। रिकॉर्ड पर कोई दुर्बलता या संदिग्ध परिस्थिति उपलब्ध नहीं है जो किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के संस्करण पर कोई संदेह पैदा कर सकती है जैसा कि मुकदमे में सामने रखा गया है। रत्नाबाई पीडब्लू 11 की नेत्र संबंधी गवाही, जो तब से गांव छोड़ चुकी है, में कोई दोष नहीं है और चूंकि हमने उसे पूरी तरह से विश्वसनीय गवाह पाया है, यह अपने आप में मनराजबाई की हत्या के लिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराने का आधार बन सकता है। उसकी गवाही में अपराध करने के समय और उसके बाद अपीलकर्ता के आचरण को भी दर्शाया गया है। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए अपीलकर्ता के स्वैच्छिक इकबालिया बयान की प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य दोनों तरह से रिकॉर्ड पर पर्याप्त पुष्टि उपलब्ध है, भले ही वह मुकदमे में मुकर गया हो।

26. इस प्रकार, रिकॉर्ड पर साक्ष्य और उपरोक्त चर्चा से, यह निष्कर्ष अपरिवर्तनीय है कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे स्थापित किया है कि अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी श्रीमती काजोदबाई और उनके पांच बच्चों की हत्या कथित तरीके से की थी। अभियोजन और, इसलिए, निचली अदालतों ने प्रत्येक मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए उसे सही ढंग से दोषी ठहराया। जैसा कि नीचे दी गई अदालतों द्वारा दर्ज किया गया है, हम उसकी सजा को बरकरार रखते हैं।

27. जहां तक सजा का सवाल है, अभियोजन मामले का वर्णन करते समय हमने प्रथम सूचना रिपोर्ट के स्वीकार्य भाग में अपीलकर्ता द्वारा दिए गए मकसद का संकेत दिया है। पी-42 और उसके इकबालिया बयान में। यह अनावश्यक रूप से संदिग्ध पति, अपनी पत्नी श्रीमती कजोड़बाई की निष्ठा पर संदेह करता था और उस पर भोजक गुजर के साथ संबंध होने का संदेह करता था, लेकिन कजोड़बाई का सिर उसके शरीर से अलग करने और इस तरह उसकी हत्या करने से नहीं रुका, बल्कि हत्या की होड़ में चला गया और अपने पांचों की हत्या कर दी। बच्चे भी बिना किसी तुक या कारण के एक के बाद एक। 2 से 14 साल की उम्र के छोटे मासूम बच्चों की बिना किसी गलती के बेहद क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई। उसने बच्चों का पीछा किया और उनकी हत्या कर दी. उनके भाई की पत्नी श्रीमती रत्नाबाई पीडब्लू 10 द्वारा कम से कम आखिरी बच्चे को छोड़ देने की विनती को भी अपीलकर्ता ने अनसुना कर दिया। अपीलकर्ता ने अत्यंत जघन्य, नृशंस और वीभत्स हत्या की। जब पशु और पक्षियों जैसी निचली प्रजातियाँ भी अपनी संतानों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाती हैं, तो अपीलकर्ता भ्रष्टाचार की इतनी गहराई तक गिर गया कि उसने अपनी ही पत्नी और बच्चों की, बिना किसी गलती के, केवल कुछ संदेह के आधार पर हत्या कर दी। उसके मन में यह बात बैठा दी गई कि उसकी मृत पत्नी का भोजक गूजर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। एक अवसर पर अपनी पत्नी की बेवफाई की अफवाह सुनकर अपनी पत्नी और पांच बच्चों की नृशंस हत्या करने का अपीलकर्ता का कृत्य हमारी रीढ़ को झकझोर देता है और हमारी न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देता है।

28. धनंजय चटर्जी बनाम स्टेट ऑफ डब्ल्यू बी 1 में सजा के सवाल से निपटते समय इस न्यायालय ने पाया कि बढ़ती अपराध दर ने अदालतों द्वारा आपराधिक सजा को चिंता का विषय बना दिया है और हालांकि कोई भी कटा हुआ और सूखा फार्मूला निर्धारित करना संभव नहीं है। सजा देने के संबंध में और आगे कहा:

> उसे सजा देने का उद्देश्य यह देखना चाहिए अपराध को सजा नहीं मिलती है और अपराध के शिकार व्यक्ति और समाज को भी संतुष्टि होती है कि उसके साथ न्याय हुआ है। विशिष्ट कानून के अभाव में सजा सुनाते समय, न्यायाधीशों को विभिन्न कारकों पर विचार करना चाहिए और उन सभी कारकों पर विचार करने के बाद निर्णय लेना चाहिए। स्थिति का समग्र दृष्टिकोण, वे जो उचित समझें, सजा दें। उत्तेजित करने वाले कारकों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और इसी तरह कम करने वाली परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा।
>
> हमारी राय में, किसी दिए गए मामले में सज़ा की माप अपराध की क्रूरता पर निर्भर होनी चाहिए; अपराधी का आचरण और पीड़ित की रक्षाहीन और असुरक्षित स्थिति। उचित सज़ा देना वह तरीका है जिससे अदालतें अपराधियों के खिलाफ न्याय के लिए समाज की पुकार का जवाब देती हैं। न्याय की मांग है कि अदालतों को अपराध के अनुरूप सजा देनी चाहिए ताकि अदालतें अपराध के प्रति सार्वजनिक घृणा दर्शा सकें। उचित सज़ा देने पर विचार करते समय अदालतों को न केवल अपराधी के अधिकारों को बल्कि अपराध के पीड़ित और बड़े पैमाने पर समाज के अधिकारों को भी ध्यान में रखना चाहिए।"

29.अपीलकर्ता ने जो बर्बर, वीभत्स और जघन्य प्रकार का अपराध किया वह समाज के विरुद्ध विद्रोह और मानवीय गरिमा का अपमान है। इस मामले में किसी भी तरह की कोई कम करने वाली या कम करने वाली परिस्थितियां नहीं हैं और न ही कोई बताया गया है और हमारी राय में यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें मृत्युदंड के अलावा किसी अन्य सजा की आवश्यकता नहीं है और हम तदनुसार अपीलकर्ता को दी गई मौत की सजा की पुष्टि करते हैं। दया के लिए उनके विद्वान वकील की दलील अनुचित है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में सहानुभूति की प्रार्थना पूरी तरह से गलत है। इसलिए, हम आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए निचली अदालतों द्वारा अपीलकर्ता को दी गई सजा और मौत की सजा को बरकरार रखते हैं।

परिणामस्वरूप, यह अपील विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

अपील खारिज

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।